भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2540

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम

†2540. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों को, हिंदी या किसी अन्य महत्वपूर्ण भाषा के सिवाय, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम का नियमन करने वाली कोई भाषा नीति है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी संस्थाओं में वर्तमान में अपनाए जा रहे भाषा के माध्यम का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष **2014** से अब तक सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर स्नातकोत्तर (पीजी) में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ.) सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण संकाय की भर्ती का, सामाजिक श्रेणी-वार, भाषा-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ.): भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 प्रस्तुत की है। इन नीति और पाठ्यक्रम दस्तावेज में स्कूल में सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। इन दस्तावेजों को हितधारकों और छात्रों की शिक्षा के बारे में चिंतित लोगों के साथ राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श के बाद विकसित किया गया है। एनईपी 2020 और एनसीएफ-एसई का उद्देश्य मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि स्कूल में सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा सके क्योंकि जब छात्र अपनी भाषाओं में सीखते हैं तो

छात्रों का संज्ञानात्मक और शैक्षणिक विकास सुचारू और सामंजस्यपूर्ण होता है। बहुभाषी शिक्षा स्कूल में भाषा शिक्षा की शिक्षाशास्त्र, नीति और लक्ष्य है।

एनईपी 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि यह भली भांति समझा जाता है कि युवा छात्र अपनी घरेलू भाषा/मातृभाषा में अधिक तेजी से गैर-मामूली अवधारणाओं को सीखते और समझते हैं। घरेलू भाषा आमतौर पर वही भाषा होती है जो मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाती है। तथापि, बहुभाषी परिवारों में कभी-कभी परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से अलग हो सकती है। जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, जहां भी संभव हो, घरेलू/स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाना जारी रहेगा। इसके बाद सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूल होंगे।

इसके अलावा, एनईपी 2020 में इस बात पर भी बल दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र को लागू करना जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा सूत्र में अधिक अनुकूलता होगी , और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। छात्रों द्वारा सीखी गई तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों की अपनी पसंद की होंगी, जब तक कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषा होंगी।

एनसीएफ-एसई 2023 में, अन्य बातों के अलावा, यह प्रावधान है कि छात्र अपने स्कूली वर्षों में कम से कम तीन भाषाएं सीखेंगे, जिन्हें आर1, आर2 और आर3 कहा जाता है।

- आर 1: यह भाषा शिक्षा के माध्यम (एमओआई) के रूप में उपयोग की जाती है, और जिसमें साक्षरता सबसे पहले प्राप्त की जाती है। अधिमानतः यह छात्रों की सबसे परिचित भाषा होनी चाहिए, जो आमतौर पर मातृभाषा / घरेलू भाषा होती है। भारत की भाषाई विविधता के साथ, यहां तक कि एक कक्षा-कक्ष के भीतर भी, सभी छात्रों के लिए आर1 के रूप में घर की भाषा होना संभव नहीं हो सकता है; ऐसी परिस्थितियों में एक भाषा जिसे छात्रों के लिए परिचित भाषा के रूप में आर1 को चुना जाना चाहिए - जो अक्सर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय भाषा होती है।

- आर 2: यह अंग्रेजी सहित कोई अन्य भाषा हो सकती है।

- आर 3: यह कोई अन्य भाषा है जो आर1 या आर 2 नहीं है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मातृभाषाओं / स्थानीय भाषाओं / घरेलू भाषाओं के लिए प्रवेश स्तर के प्राथमिक की उपलब्धता, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग और एनसीएफ-एसई 2023 के तहत आधारभूत और प्रारंभिक चरणों के लिए भाषा निर्देश के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों के लिए परिपत्र जारी किए हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

- https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2023/84_Circular_2023.pdf
- https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2024/43_Circular_2024.pdf
- https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2025/30_Circular_2025.pdf

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि शिक्षण-अधिगम को सुविधाजनक बनाया जा सके और छात्रों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में परीक्षा लिखने में सक्षम बनाया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, यूजीसी ने दिनांक 13.07.2023 के अपने पत्र के माध्यम से सभी एचईआई को भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के अनुवाद के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, भारतीय भाषा में सामग्री निर्माण का एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, यूजीसी ने भारतीय भाषा समिति के सहयोग से उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक लेखन और अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता नामक एक परियोजना की परिकल्पना की है।

इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की एक भाषा नीति है जो एनईपी 2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं (मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषाओं) के उपयोग को बढ़ावा देती है।

भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण संकाय की भर्ती संबंधित भर्ती प्राधिकरणों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, जो लागू होने वाले विभिन्न सामाजिक श्रेणियों, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए सरकार के मौजूदा प्रावधानों और आरक्षण नीतियों के अनुसार होती है।

इसके अलावा, चूंकि शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल और कॉलेज राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधीन हैं, इसलिए राज्य और संघ

राज्य क्षेत्र अपने संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के माध्यम और शिक्षण संकाय की भर्ती के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए सुव्यवस्थित हैं।

*****